ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

अगर खत्म हो गई तितलियां? तो चॉकलेट, सेव, कॉफी भी नसीब नहीं होंगे

रविवारीय, 31 जन.-06 फरवरी 2021 वर्ष- दो, अंक-26, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

ऑटोमोबाइल कचरा बना चुनौती

तेजस सूर्या नाइक शोधपत्र ''इंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स मैनेजमेंट एट इंडियन ऑटोमोबाइल सिस्टम'' बताता है कि दुनियाभर में ऑटोमोबाइल का कचरा चुनौती बन चुका है। 2010 में वाहनों का स्वामित्व 100 करोड़ पार हो चुका है। भारत में 2010 में 11 करोड़ वाहन सड़कों पर चल रहे थे। 2010 से 2015 तक बीच अतिरिक्त 10.3 करोड़ वाहनों का उत्पादन किया गया। सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के मुताबिक, भारत में इस समय 22.95 करोड़ वाहनों का पंजीकरण है। अनुमान है कि 2030 तक 31.5 करोड़ वाहन सड़कों पर होंगे। वाहन पर्यावरण प्रदूषित के साथ ही पारिस्थितिक संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। एक कार में 70 प्रतिशत इस्पात और 7-8 प्रतिशत एलुमिनियम होता है। शेष 20-25 प्रतिशत हिस्सा प्लास्टिक, रबड़, कांच, आदि होता है। अगर पर्यावरण अनुकूल और वैज्ञानिक तरीके से रिसाइक्लिंग की जाए तो इनमें से अधिकांश चीजें दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं।

पर्यावरण अनुकूल बजट

ग्रीन रिवोल्ट न्यूज

इस साल का बजट कई मायनों में अलग और एतिहासिक है। कोरोना काल में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। विपक्ष के साथ ही देश की जनता को भी इंतजार था कि जब दिल्ली के बॉर्डरों पर जब किसान आंदोलित हैं साथ ही यह खबर भी आयी कि देश के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान बढा है ऐसे में केंद्र सरकार और वित्त मंत्री किसानों और कृषि क्षेत्र के प्रति क्या रवैया रखेंगी। जब बजट का पिटारा खुला तो जानकारों का कहना है कि यह बजट पर्यावरण , प्रदूषण के अनुकूल साथ ही कृषि क्षेत्र के लिये मिश्रित है। पुराने वाहनों के लिये नयी स्क्रैप पॉलिसी , वायुप्रदूषण दूर करने के लिये योजनाओं की घोषणा की गयी हैं वहीं शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब यह देखना होगा कि यह सारी पर्यावरणुकूल योजनायें कितनी सफलता से धरातल पर उतरती हैं?

कृषि के लिये क्या है?

वित्त मंत्री ने कहा कि मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर केंद्रित रही है। उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि धान खरीदारी पर 2013-14 में 63 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस बार यह बढ़कर 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए हो चुका है इसके अलावा 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं 2019 में 63 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी की गई थी जो बढ़ कर अब लगभग 75 हजार करोड़ रुपए हो गई है। वहीं दूसरी ओर दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्च किए गए थे। इसे इस साल 10 हजार 500 करोड़ रुपए की खरीदारी की जाएगी। इसमें 40 गुना इजाफा हुआ है। वित्तमंत्री ने बताया कि 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका फायदा मिला। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। एमएसपी को बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

वित्त मंत्री ने वायु, जल और परिवहन से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की

कोविड -19 महामारी के दौर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। वित्तमंत्री ने कहा कि मुश्किल हालात में यह बजट पेश हो रहा है। बजट कोरोना काल में तैयार किया गया। यह बजट ऐसे वक्त में आ रहा है, जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में गई है, लेकिन यह ग्लोबल इकोनमी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि साल 2021 ऐतिहासिक साल साबित होने जा रहा है। अपने लंबे बजट भाषण के दौरान उन्होंने पर्यावरण से जुड़ी कई घोषणाएं कीं। इनमें से जल जीवन मिशन, वायु प्रदूषण और परिवहन से जुड़ी कई घोषणाएं शामिल हैं। बजट में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रस्ताव किया गया है। वित्तमंत्री के अनुसार अगले पांच साल में दो हजार करोड़ रुपए से अधिक क्लीन एयर पर खर्च किए जाएंगे। स्वच्छ हवा के लिए देशभर के दस लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों पर 2,217 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। इससे प्रदूषण नियंत्रित होगा। देश भर में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। निजी गाड़ी को 20 साल बाद इन सेंटर पर ले जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का एलान किया, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किया गया है।

पुराने वायु प्रदूषक वाहनों को खत्म करने के लिये स्क्रैप पॉलिसी

वाहन स्क्रैप पॉलिसी (पुराने वाहनों को हटाने की नीति) लाने जा रही है। इस नीति के तहत पुराने वाहनों को निश्चित समयकाल के बाद सड़कों पर चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद इन वाहनों को स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने नई स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि यह ऑटो सेक्टर को एक बड़ा है। क्योंकि पुराने वाहनों के सड़क से गायब हो जाने से ऑटो सेक्टर में वाहनों की बिक्री में तेजी देखने को मिलेगी। कोरोना काल के दौर में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में ऑटो सेक्टर सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

बताया गया है कि इस पॉलिसी के ऐलान से ऑटो सेक्टर में वाहनों की बिक्री बढ़ेगी और इस सेक्टर में हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों हुए एक कार्यक्रम के दौरान इस तरह के संकेत दे दिए थे। पिछले साल सरकार ने बिजली के वाहनों को अपनाने के लिए 15 साल से पुराने वाहनों को खत्म करने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधनों का प्रस्ताव किया था। बीते वर्षों में प्रदूषण भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है।

कई बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक रहा कि बुजुर्ग एवं बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने नई स्क्रैप पॉलिसी लाने का ऐलान किया है। देशभर में पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। वाहन पुराने हो जाने पर अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। सरकार का दावा है कि नई स्क्रैप पॉलिसी के आने से सड़कों से पुराने वाहन गायब हो जाएंगे और प्रदूषण के स्तर में भी कमी देखने को मिलेगी। सरकार की इस पहल से लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ेगा जो कि प्रदूषण कम करने के लिहाज से बहुत आवश्यक है।

6.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है समुद्र का तापमान

एजेंसियां : अध्ययनकर्ताओं ने पता लगया कि पिछले 40 वर्षों में, उत्तरी प्रशांत के कुछ क्षेत्रों में समुद्र की सतही परत लगभग 3 मीटर तक पतली हो गई है। सन 2100 तक मिश्रित परत 4 मीटर पतली होने का अनुमान लगाया है। अमेरिका स्थित कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि समुद्र की सतह की "मिश्रित परत" हर साल पतली होती जा रही है। यह जितनी पतली होगी उतनी ही अधिक गर्म होगी। यह अध्ययन हाल के चरम समुद्री हीटवेव के बारे में विस्तार से बताता है और भविष्य में अधिक लगातार और विनाशकारी महासागरीय गर्म होने की घटनाओं की ओर इशारा करता है क्योंकि वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है।

प्रमुख अध्ययनकर्ता डिलन अमाया ने कहा भविष्य में समुद्री हीटवेव अधिक तीव्र और बार-बार होगें। अब हम इस प्रक्रिया को समझ रहे हैं कि कैसे जब मिश्रित परत पतली होती है, तो यह कम गर्मी को ग्रहण करती है जिससे समुद्र अधिक गर्म हो जाता है। मिश्रित परत - पानी जिसमें तापमान लगातार स्थिर बना रहता है, जो समुद्र के शीर्ष 20-200 मीटर को आवरण देता है। इसकी मोटाई गर्मी की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। यह जितनी अधिक मोटी होती है, इसकी उतनी ही अधिक परतें आने वाली गर्म हवा से नीचे के पानी के लिए ढाल के रूप में कार्य कर सकती है। लेकिन कवच के रूप में, मिश्रित परत तेजी से बढ़ते तापमान को ग्रहण कर लेती है।

अमाया ने कहा कि मिश्रित परत पानी को एक बर्तन में उबालने की तरह है। एक इंच पानी में उबाल आने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, लेकिन यदि बर्तन ज्यादा भरा हो तो गर्म होने, उबलने में अधिक समय लगेगा। अमाया और उनकी टीम ने 1980 तक मिश्रित परत की गहराई का अनुमान लगाने के लिए समुद्र का अवलोकन और मॉडल का उपयोग किया और भविष्य के लिए भी परत के बारे में अनुमान लगाया। उन्होंने पता लगया कि पिछले 40 वर्षों में, उत्तरी प्रशांत के कुछ क्षेत्रों में समुद्र की सतह की परत लगभग 3 मीटर तक पतली हो गई है। सन 2100 तक मिश्रित परत 4 मीटर पतली होने का अनुमान लगाया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह पतली मिश्रित परत दुनिया भर के तापमान के साथ-साथ समुद्र के तापमान में भारी बदलाव के लिए मंच तैयार करेगी।

.....शेष पेज तीन पर

श्मशान घाट को भी नहीं बख्श रहे हैं रेत माफिया

बालू खनन रोकने के लिये बैठक करते ग्रामीण

संवाददाता

श्मशान घाट से बालू का खनन, रोकने के लिए ग्रामीणों ने की बैठक

रांची/बुंडूः नदियों से अवैध बालू खनन इस कदर जारी है रेत माफिया नदी किनारे के श्मशान घाट को भी नही छोड़ रहे हैं। मामला बुंडू अंचल के राजस्व ग्राम एडकेया का है। गांव कांची नदी के किनारे है और इस गांव का श्मशान घाट कांची नदी के किनारे ही है। बालू के अवैध खनन से इस श्मशान घाट का अस्तित्व आज खतरे में है।वजह श्मशान घाट के करीब बालू की खुदाई। शाम ढलते ही जेसीबी मशीन उतार दी जा रही है। मशीन से अंधाधुंध बालू का खनन किया जा रहा है।इस तरह बालू के खनन से ग्रामीण चिंतित हैं। चिंता वाजिब है रेत के इस तरह के

खनन से श्मशान में दफनाए गए शव ना निकल जाए! चिंता इस बात की भी है कि श्मशान घाट की जमीन रेत के खनन से कम हो रही है ।

गांव वाले भविष्य में शव कहाँ दफ़नाएगे ?

इसी खतरे को देखते हुए 28 जनवरी को श्मशान घाट के जगह पर ही 'महतो' महिंदर महतो की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में एड़केया गांव के ग्रामीण शामिल हुए। बैठक में श्मशान घाट को बचाने को लेकर चर्चा हुई। श्मशान घाट के करीब बालू उठाव न हो ! साथ ही श्मशान घाट की सीमा को लेकर भी चर्चा हुई।

बैठक स्थल में श्मशान घाट बचाने के लिए अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, खनन सचिव के नाम आवेदन लिखा गया, सभी ग्रामीण आवेदन पर हस्ताक्षर किए।

कोयला के मुकाबले उद्योगों में बिजली और प्राकृतिक गैस को दें तरजीह

एजेंसियां :पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा है कि बजट 2021 में स्वच्छ ईंधन को प्रोत्साहित करके वायु प्रदूषण की लड़ाई को प्रभावी बनाया जा सकता है।

वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए उद्योगों के जरिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बेहद कारगर रणनीति साबित हो सकती है। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक ईकाइयों के जरिए बड़े पैमाने पर प्रदूषण के लिए प्रबल तरीके से जिम्मेदार कोयला ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में बजट-2021 में स्वच्छ ईंधन को यदि बढ़ावा दिया जाता है तो वायु प्रदूषण की लड़ाई न सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के लिए बल्कि समूचे देश के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट (सीएसई) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट 2021 में स्वच्छ ईंधन को औद्योगिक इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन देने के प्रावधान की अपील की है। सीएसई ने अपनी अपील में कहा है कि कोयला के मुकाबले उद्योगों को बिजली और प्राकृतिक गैस को इंसेंटिव देकर प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए। इस कदम से न सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में बल्कि देशभर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने पत्र में कहा है कि प्राकृतिक गैस पर अभी कर का बोझ काफी अधिक है। मसलन राज्यों में प्राकृतिक गैस की बिक्री और खरीद दोनों बिंदु पर टैक्स लगाया जा रहा है। इसके चलते अंतिम कीमत में 18 फीसदी या उससे अधिक की बढोत्तरी हो रही है। जैसे कोयला (पांच फीसदी) जीएसटी में शामिल है वैसे नैचुरल गैस जीएसटी में शामिल नहीं है। बीते वर्ष कुल पेट्रोलियम उत्पादों में नैचुरल गैस के जरिए टैक्स की हिस्सेदारी का राजस्व गुजरात में करीब-करीब 20 फीसदी और महाराष्ट्र में 7 फीसदी रहा है।

विनय रंजन, ''सीएचआरओ ऑफ द ईयर अवार्ड'' से सम्मानित

रांची संवाददाता : 30 जनवरी को कोलकाता में आयोजित 'एचआरडी इंडिया अवार्डस समारोह' में विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल एवं ईसीएल को 'सीएचआरओ ऑफ द ईयर अवार्ड' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार श्री रंजन को मानव संसाधन सेवा में व्यापक व्यहवारिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किया गया।

अवसर विशेष पर विनय रंजन ने कहा कि यह अवार्ड से निश्चय ही सीसीएल परिवार का मनोबल बढ़ेगा और हमें इस दिशा में और अधिक उत्साह के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित भी करेगा। ज्ञातव्य है कि सीसीएल एवं ईसीएल के निदेशक (कार्मिक) के रूप में विनय रंजन ने कोरोना के कठिन समय में भी कर्मियों को प्रेरित किया और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सेवा जैसे सूखा अनाज, एवं अन्य राहत समग्रीयों का वितरण किया गया। इसी तरह सीसीएल एवं ईसीएल में कल्याणकारी योजनाओं का कार्यन्वयन किया जा रहा है। निदेशक (कार्मिक) के नेतृत्व में सीसीएल एवं ईसीएल के प्रगति एवं विकास में अपनी अहम भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है। विनय रंजन सीसीएल के अतिरिक्त प्रभार में निदेशक (कार्मिक) के रूप में लगभग छः महिने से कार्य कर रहे हैं।

अगर आस पास हैं पेड़ पौधे तो नहीं होंगे अवसादग्रस्त

मुरलीधर

मानसिक स्वास्थ्य पर हुए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि घर के आसपास पेड़ होने से लोगों में अवसाद से उबरने की संभावना ज्यादा होती है. पेड़ों के अगिनत फायदे होते हैं. लेकिन इस सूची में शायद अब तक डिप्रेशन या निराशा से उबरना भी शामिल हो जाएगा. जर्मनी के लाइपसिग के 9751 निवासियों पर हुए अध्ययन से इस तरह के पक्के संकेत मिले हैं. समुदायों के मानसिक स्वास्थ्य को सही तरह से जानने के लिए शोधकर्ताओं ने लोगों की ओर से दी गई जानकारी के बजाय एंटी डिप्रेसैंट नुस्खों का आंकलन किया. इसके बाद उन्होंने लोगों के इलाके में गलियों में पड़ों की संख्या के आकड़ों से तुलना की.

शोध में पाया गया कि लोगों के घर से सौ मीटर के अंदर स्थानीय वनस्पति का एंटी डिप्रेसैंट नुस्खा लेने की संभावना कम होने से संबंध है. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह पड़ताल शहरी नियोजनकर्ता स्वास्थ्य व्यवसायी और सरकार के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी. गलियों के पेड़ों का एंटीडिप्रैसेंट लेने की कमी का खास तौर पर सामाजिक आर्थिकरूप पिछड़े वर्ग समूह में ज्यादा नाता दिखाई दिया. वैसे इन नतीजों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता. लेकिन ये यह संकेत तो देते ही हैं कि शहरी पेड़ सामान्य तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का आसान और किफायती तरीके के तौर पर उपयोगी हो सकते हैं. इसके अलावा वे समाज में स्वास्थ्य असामानता को कम करने में सहायक हो सकते हैं.

यूके में डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी की पर्यावरण मनोवैज्ञानिक मेलीसा मर्सेले का कहना है, ''हमारी पाड़ताला सुझाती हैं कि शहरी की गलियों के पेड़ जो लोगों की पहुंच के दायरे में हों, आर्थिक रूप से अलग अलग समाजिक समूहों में स्वास्थ्य असमानता के अंतर को कम करने में मदद कर सकते हैं. यह एक अच्छी खबर है क्यों कि ऐसे पेड़ों तक पहुंचना आसान है और उनके संख्या भी बिना किसी खास नियोजन के बढ़ाई जा सकती है.

जब शोधकर्ताओं ने डिप्रेशन के जोखिमों को कम करने के दूसरे कारक देखे जैसे कि रोजगार, लिंग, आयु, और वजन जैसे दूसरे कारक देखे तो सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभकारी समूहों के बाहर गलियों के पेड़ों का कारक केवल मामूली तौर पर प्रभावी था. इससे उन्हें यह पता चला कि जिन लोगों को डिप्रेशन के मामले में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वे ज्यादातर प्रकृतिक वातावरण से हासिल कर लेते हैं. शोधकर्ताओं ने पाया कि 100 मीटर की दूरी बहुत अहम थी. आसपास की गलियों के इलाके में ज्यादा पेड़ों के होने से एंटीडिप्रैसेंट नुस्खों की दर पर ज्यादा असर नहीं पड़ा. वहीं शोधकर्ताओं ने यह भी पाया की पेड़ों भी मायने नहीं रखती. जहां इस अध्ययन की अपनी सीमाएं हैं सभी निराशा से पीड़ित व्यक्ति भी एंटीडिप्रैसेंट का उपयोग नहीं करते हैं. मानसिक स्वास्थ्य को असर करने का काम दूसरी तरह के कारक भी कर सकते हैं लेकिन आंकड़े बताते हैं कि गलियों के पेड़ का उस इलाके के लोगों का दैनिक जीवन में मूड बेहतर करने में पर्याप्त संबंध है।

जर्मन सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव बायोडाइवर्सिटी रिसर्च में पॉप्यूलेशन इकोलॉजिस्ट डायना बोउलर ने बताया, अहम बात यह है कि शहरी हरितक्षेत्र के लिए ज्यादातर योजना मार्गनिर्देशन प्रायः मनोरंजन के लिए उद्देश्यपूर्ण मुलाकातों के आधार पर होती है. हमारा अध्ययन दर्शाता है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि घर प्रकृति के करीब हो, जब आप खिड़की खोलें, या जब टहल रहे हैं या काम, शॉपिंग आदि के लिए जा रहे हों तो आपको जैविविधता दिखे. कोविड-19 के लॉकडाउन के दौर में यह बहुत प्रासंगिक हो गया है.

आज वैश्विक महामारी के दौर में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और उससे संबंधित मुद्दे गंभीर हो रहे हैं. इससे निपटने में सहायता के तौर पर शोधकर्ता दैनिक जीवन में निर्बाध प्राकृतिक अनुभव से जुड़ने की बात करते हैं. शोधकर्ता यह भी सलाह देते हैं कि भविष्य के अध्ययनों में किसी जगह पर डिप्रेशन जोखिम पर दूसरे तरह के हरितक्षेत्र और उनके प्रभाव को शामिल करेंगे. इसके अलावा वे पड़ों के आकार प्रकार को भी अपने अध्यन में शामिल करेंगे.

यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है. शोधकर्ताओं एलेटा बोन का कहना है, ''हमारा प्रस्ताव है कि रिहायशी शहरी इलाकों में गलियों के पेड़ बढ़ाना एक प्रकृति आधारित समाधान होगा जो न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के असर को भी कम करेगा और जैविविधता संरक्षण में भी योगदान देगा.'' यह समाधान शहरों को ठंडा, तनाव स्तर को कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में भी काम आएगा।

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

भरोसा खो चुका आंदोलन

वर्तमान कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ में वाजिब लग रहा था। लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि यह आंदोलन किसानों के जायज शंकाओं , मांगों के बजाय पूर्णतः राजनीतिक है। किसान नेताओं की करतूत, उनके झूठ, भीड़ के सामने दिये उनके उन्मादी बयान और गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में तोड़- फोड़ , हिंसा में उनकी संलिप्तता यह जाहिर करती है कि आंदोलन का मकसद राजनीतिक ज्यादा है ।

क्या पांच लाख ट्रैक्टर को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा देने से कृषि बिल की शंकाओं का निवारण हो जायेगा? या खाप पंचायत कर जाति विशेष के लोगों के हुजूम से? एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि कृषि कानूनों के विरोध का यह आंदोलन इसके नेतृत्वकर्ताओं की गलत मंशा, हिंसा और जिद के कारण अब अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। भले ये लोग पैंतरेबाजी कर उन्मादी भीड़ इकट्ठा कर लें, ताकत दिखा लें, पर 26 जनवरी के दिन के करतूत से ये भरोसा खो चुके हैं।

कृषि कानूनों में क्या कमी है वो किसान नेता बतायें हम उस पर विमर्श करेंगे।केंद्र सरकार ने ऐसा कहकर ये संदेश तो देश की जनता को दे ही दिया कि वह वार्ता के लिये सदैव तैयार है। वहीं आंदोलनकारी नेताओं की जिद से उनकी यह नकारात्मक छवि बनी है कि ये लोग किसान हित में समाधान के बजाय सिर्फ सरकार को झुका कर सिर्फ नीचा दिखाना चाहते हैं?

संभव है कि इन कृषि कानूनों में खामियां भी हों , किसानों का भय जायज हो लेकिन इसका निदान वास्तव में बातचीत से ही संभव है , बशर्ते सरकार से ये बात चीत अच्छी मंशा से की जाये। अब तक कितनी ही बार वार्ता की गयी, पर आंदोलनकारी किसान नेताओं ने सिर्फ एक ही जिद पकड़े रखी कि पहले तीनो कृषि कानून को सरकार रद्द करें ? एक लोकतांत्रिक देश में दोनो सदनों से पास किसी कानून को सिर्फ कुछेक हुड़दंगियों के तोड़ फोड़ और विरोध के बाद रद्द कर देने से भी एक गलत संदेश जायेगा। इसके बाद देश में सदन से पास कराये गये किसी भी बिल को उसके मुट्ठी भर विरोधी हिंसात्मक विरोध कर उसे रद्द कराने पर उतारू हो जायेंगे ?

गणतंत्र दिवस के दिन हिंसात्मक विरोध के बाद इस आंदोलन की अंदरूनी ताकत खत्म हो चुकी है। इसने स्वतः प्राप्त जनसमर्थन भी खो दिया है। अब यह क्षेत्र विशेष, जाति और व्यक्ति विशेष के शक्तिप्रदर्शन का जरिया बनते जा रहा है। इसके अलावा इस आंदोलन में निश्चय ही देशद्रोही तत्व घुस आये हैं। बाहर से करोड़ो की फंडिंग के अलावे विध्वंसक तत्वों के शामिल होने के आरोप को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। जनता भी जान रही है कि सिर्फ लाखो ट्रैक्टर को दिल्ली में दौड़ा देने भर से किसान हित पूरा नहीं होगा।

कोविड-19 के चलते 37 करोड़ बच्चों को नहीं मिल सका स्कूलों में भोजन

कोविड-19 और उसके चलते होने वाले लॉकडाउन के कारण 199 देशों के करीब 160 करोड़ विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। यह मामला सिर्फ उनकी शिक्षा का ही नहीं है यह उनके पोषण से भी जुड़ा है, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में स्कूल बच्चों को जरुरी पोषण और भोजन उपलब्ध कराते हैं।

भारत की मिड डे मील योजना भी उनमें से एक है। जिसके अंतर्गत बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए स्कूलों में मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि स्कूलों के बंद होने के कारण 150 देशों के 37 करोड़ बच्चों को स्कूल में भोजन नहीं मिल पाया था। यह जानकारी हाल ही में यूनीसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा सम्मिलित रूप से जारी रिपोर्ट में सामने आई है। यदि 2019 के लिए जारी आंकड़ों पर गौर करें तो इनके अनुसार दुनिया के 55 देशों में स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है। यहां के 13.5 करोड़ लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, जबकि 200 करोड़ लोगों को अभी भी पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। ऐसे में कोविड-19 महामारी ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। अनुमान है कि इस महामारी के चलते 2020 के अंत तक और 12.1 करोड़ लोग खाद्य संकट का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे।

गौरतलब है कि अब तक दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के 10 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इसके कारण 21 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी इस महामारी के एक करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में 5 वर्ष से छोटे करीब 14.4 करोड़ बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से ठिगने हैं, जबकि इस महामारी के कारण उनकी संख्या में 34 लाख का और इजाफा कर देगा। इसी तरह 5 से 19 वर्ष की 7.4 करोड़ बच्चियां और 11.7 करोड़ लड़के लम्बाई के हिसाब से पतले हैं। ऐसे में स्कूलों में मिलने वाला भोजन उनके पोषण के लिए कितना जरुरी है इस बात को आप खुद ही समझ सकते हैं।

28 फीसदी शहरी परिवार अभी भी कर रहे हैं अपने भोजन में कटौती

लॉकडाउन में केवल 26 फीसदी पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ा था। जबकि 55 को अपनी नौकरी दोबारा मिल गई है। लेकिन 15 फीसदी को अभी भी अपना काम वापस नहीं मिला है, वहीं 5 फीसदी श्रमिकों ने लॉकडाउन के बाद अपनी नौकरियों को गंवा दिया है। यदि महिला श्रमिकों की तुलना पुरुष श्रमिकों से करें तो उनकी स्थिति ज्यादा बदतर है। जहां 57 फीसदी पुरुषों को उनका काम वापस मिल चुका है, लेकिन इसकी तुलना में केवल 53 फीसदी महिला श्रमिक ही काम पर वापस लौट पाई हैं। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो शहरी क्षेत्रों पर इसका ज्यादा असर पड़ा है।

10 में से 9 घरों में लॉकडाउन के दौरान अपने भोजन में कटौती करनी पड़ी थी। केवल एक तिहाई घरो की स्थिति पहले जैसी हो पाई है। शहरी परिवारों की स्थिति ज्यादा बदतर है। 15 फीसदी ग्रामीण घरों की तुलना में अभी भी 28 फीसदी शहरी घरों में खाने की खपत अभी भी लॉकडाउन के जितनी ही है।

कैसे रखें पृथ्वी के फेफड़े अमेजन वनों का ख्याल ?

ब्राज़ील में पर्यावरण बजट का हुआ बुरा हाल?

बोल्सनारो को यूं ही नहीं पर्यावरण विरोधी नहीं कहा जाता। बोल्सनारो प्रशासन एक बार फिर अपनी पर्यावरण विरोधी नीति के लिए सुर्खियों में है।ब्राज़ील के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 2021 का बजट पिछली शताब्दी के अंत के बाद से अब तक का सबसे कम बजट है। मौजूदा बजट प्रस्ताव बोल्सनारो प्रशासन द्वारा अपनाई गई पर्यावरणीय विघटन रणनीति को फिर से रेखांकित करता है।

दरअसल ब्राज़ील के पर्यावरण मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित 2021 का बजट पिछली शताब्दी के अंत के बाद से सबसे कम है। इस साल का वार्षिक बजट विधेयक प्रस्ताव (प्लोआ), जो फरवरी में कांग्रेस में पारित होने वाला है, सभी एमएमए खर्चों को कवर करने के लिए, जिसमें वेतन और पेंशन जैसे अनिवार्य ख़र्चे हैं, को $ 1.72 बिलियन (313 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का अनुदान देता है। ऐतिहासिक श्रृंखला में, वर्ष 2000 के बाद से, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित राशि कभी भी $ 2.9 बिलियन (529 मिलियन अमरीकी डॉलर) से कम नहीं रही है, जो मुद्रास्फीति के लिए समायोजित है। डाटा ऑब्सरवाटोरिओ डो क्लाईमा द्वारा किए गए विश्लेषण से बात सामे आयी है। ध्यान रहे ब्राज़ील में दुनिया का फेफड़ा कहा जाने वाला पृथ्वी का सबसे बड़ा वर्षावन, अमेज़न, जिसे बोल्स्नारो की नीतियों के चलते लगातार नुक्सान हो रहा है।

बीते शुक्रवार (22 जनवरी) को जारी की गई ''पुशिंग दा होल लौट थ्रू'' रिपोर्ट, वर्ष 2020 के आंकड़ों के साथ, जैयर बोल्सनारो प्रशासन द्वारा बनाए गए पर्यावरण कहर के दूसरे वर्ष की जांच पड़ताल करती है। 2019 में, ओसी ने मैड्रिड में रिपोर्ट का पहला संस्करण जारी किया, जिसका शीर्षक था "दा वर्स्ट इज़ येट टू कम" ("सबसे बुरी स्थिति अभी आना बाकी है")। नई रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा अपने 2018 के चुनाव अभियान के दौरान किए गए वादों, यानी पर्यावरणीय सक्रियता को समाप्त करने और एमएमए को खत्म करने के वादों, को सख्ती से लागू किया जा रहा है। लगातार दो साल से बढ़ हुई वनों की कटाई और आग के बावजूद, सरकार ईबामा और इंस्टीट्यूटो चिको मेंडेस (ब्राजील की राष्ट्रीय उद्यान सेवा) दोनों को देखते हुए पर्यावरणीय निरीक्षण और जंगल की आग से लड़ने के लिए बजट में प्रस्तावित 27.4% की कमी के साथ 2021 शुरू करती है। 2020 में मौजूदा प्रशासन ने जो ब्राजील राज्य का हिस्सा थे उन सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण संरचनाओं के विघटन को गहरा कर दिया, नियमों को समाप्त और पर्यावरण प्रबंधन कर्तव्यों को त्याग कर।

निधियों में कटौती अन्य कार्यों के साथ आती है, जैसे टिम्बर (लकड़ी) के निर्यात पर नियंत्रण को कम करना, सैन्य पुलिस अधिकारियों को पर्यावरण एजेंसियों में पदों का आवंटन और चिको मेंडेस संस्थान के खंडन का प्रस्ताव। स्वास्थ्य, राजनीतिक अभिव्यक्ति और राज्य प्रबंधन के कई अन्य क्षेत्रों के अलावा, अमेज़न को सेना को सौंपने के लिए भी, खराब परिणामों के साथ, जनसंपर्क का प्रयास किया गया है। हालांकि, "पुश दा होल लौट थ्रू" के प्रयासों को संस्थानों, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। मारसियो अस्ट्रिनी, ऑब्सरवाटोरिओ डो क्लाईमा के कार्यकारी सचिव, कहते हैं

रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले दो वर्षों में, ब्राजील में पर्यावरण और जलवायु के एजेंडे को एक भयावह पैमाने पर अकल्पनीय असफलताओं का सामना करना पड़ा है। बोल्सनारो ने पर्यावरण के विनाश को एक नीति के रूप में अपनाया और हमारे बायोम की रक्षा के लिए उपकरणों को तोड़फोड़ किया; वह आग, वनों की कटाई और राष्ट्रीय उत्सर्जन में वृद्धि के लिए सीधे जिम्मेदार है। स्थिति गंभीर है क्योंकि संघीय सरकार, जो एक मात्र इकाई है जो इस परिदृश्य के लिए समाधान कर सकती है, अब अब समस्याओं का मुख्य कारण बनी है ''

सुअली अजारो, ऑब्सरवाटोरिओ डो क्लाईमा में वरिष्ठ सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ, कहते हैं:

''बोल्सनारो सरकार, पर्यावरण नीति के संबंध में अपने अभियान के वादों को व्यवहारिक रूप में पूरा कर रही है। पर्यावरण / प्रत्यक्ष प्रशासन मंत्रालय ने सार्वजनिक नीतियों के निर्माता के रूप में कम भूमिका निभाने का किरदार लिया है, और वर्तमान में ये व्युत्पन्न मूल्य पैदा कर रहा है जो इसके स्वयं के अस्तित्व को भी औचित्य साबित नहीं करता है। गणराज्य के राष्ट्रपति और अन्य प्राधिकारियों के कथन से ईबामा कमजोर और प्रत्यायोजित होता है। इसके अलावा, इस बात के प्रमाण हैं कि इस वर्ष की पहली छमाही में इंस्टीट्यूटो चिको मेंडेस को समाप्त कर दिया जाएगा, जो कि एक कदम पीछे की ओर है जिसे हम अनुमति दे ही नहीं सकते हैं। यह एक आने वाली विनाश की परियोजना है। **क्लाइमेट कहानी**

रिपोर्ट के कुछ मुख्य अंश

- पर्यावरण क्षेत्र (एमएमए और संबंधित संस्थाओं) के लिए पूरे उपलब्ध बजट (अनिवार्य और विवेकाधीन) का एक ऐतिहासिक विश्लेषण बताता है कि 2021 (फ $ 1.72 बिलियन) के लिए व्यय का पूर्वानुमान दो दशकों में सबसे कम है।
- सरकार द्वारा कांग्रेस को सौंपे गए वार्षिक बजट विधेयक प्रस्ताव (प्लोआ) के विश्लेषण से पर्यावरणीय निरीक्षण और जंगल की आग से लड़ने के लिए संघीय बजट में 27.4 % की गिरावट तब दिखाई देती है जब इसकी तुलना 2020 में अनुदान की गई राशि से होती है। 2019 के संबंध में यह गिरावट और भी अधिक है: 34.5%।
- 2021 के लिए प्रस्तावित बजट में वर्तमान प्रशासन की रणनीति की पुष्टि की जाती है ताकि ईबामा के निरीक्षण प्राधिकरण को दबाना जारी रखा जा सके और व्यवहारिक रूप से, क्छ्टइङ्म (आईसीएम बायो) की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए: 2018 के बजट की तुलना में संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण और प्रबंधन के लिए विशेष रूप से निर्धारित फंड में 61.5% की कटौती की गई।
- 2020 में ईबामा द्वारा लगाए गए जुर्माने की कुल संख्या भी दो दशकों में सबसे कम थी: पिछले वर्ष की तुलना में 20% और 2018 की तुलना में 35% (टेमर प्रशासन के दौरान) की गिरावट हुई।
- वनों की कटाई में नवीनतम वृद्धि - 2020 में 9.5%, 2019 में 34% वृद्धि के बाद - कानूनी अमेजन के नौ राज्यों में वनस्पतियों के खिलाफ उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माना में 42% की गिरावट के साथ ये मेल खाता है।
- स्वदेशी विरोधी प्रवचन क्षेत्र में गूंज उठे, विशेष रूप से अमेज़ॅन में: 2019 में स्वदेशी भूमि पर आक्रमण 135% बढ़ा। स्वदेशी मिशनरी परिषद के अनुसार 256 मामले दर्ज किए गए।
- भूमि पादरी आयोग के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2020 में क्षेत्र संघर्ष में कम से कम 18 लोग मारे गए।

ऑब्सरवाटोरिओ डो क्लाईमा के बारे में: 2002 में गठित एक नेटवर्क, जो 56 ब्राजीलियाई नागरिक समाज संगठनों से बना है, यह देश में और विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर बातचीत, सार्वजनिक नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्रगति लाने के लिए काम करता है।

जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में स्वैच्छिक कार्बन बाज़ारों का विस्तार ज़रूरी

पैरिस समझौते के क्रम में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक है कि वैश्विक वार्षिक ग्रीनहाउस-गैस उत्सर्जन में 2030 तक वर्तमान स्तर के 50 प्रतिशत की कटौती की जाए और साथ ही 2050 तक उसे नेट ज़ीरो के स्तर तक लाया जाए। लेकिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक गहरी और व्यापक कार्रवाई ज़रूरी है। ऐसी कार्रवाई जिसे कम उत्सर्जन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में तुरंत शुरू होना चाहिए। चूंकि अब एक बढ़ती संख्या में कंपनियां नेट ज़ीरो, या शुद्ध-शून्य उत्सर्जन स्तर, तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए उनसे ये उम्मीद भी की जाएगी कि वो दिखाएँ कि वे कार्बन क्रेडिट का उपयोग करके सीधे उत्सर्जन में कमी और उत्सर्जन ऑफसेट के उचित मिश्रण के साथ इन लक्ष्यों को पूरा करने की योजना कैसे बना रहे हैं।

आगे बढ़ने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है। कार्बन क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है । कार्बन क्रेडिट सही मायने में आपके द्वारा किये गये कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रयास है जिसे प्रोत्साहित करने के लिए धन से जोड़ दिया गया है । भारत और चीन सहित कुछ अन्य एशियाई देश जो वर्तमान में विकासशील अवस्था में हैं, उन्हें इसका लाभ मिलता है क्योंकि वे कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए UNFCCC (यूनाईटेड नेशनस फ्रेम वर्क कनेक्शन आन क्लाइमेट चेंज) से संपर्क कर उसके मानदंडो के अनुरूप निर्धारित कार्बन उत्सर्जन स्तर नियंत्रित कर सकते हैं । और यदि आप उस निर्धारित स्तर से नीचे, कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं तो निर्धारित स्तर व आपके द्वारा उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर आपकी कार्बन क्रेडिट कहलाएगा । इस कार्बन क्रेडिट को कमाने के लिए कई उद्योग धंधे कम कार्बन उत्सर्जन वाली नई तकनीक को अपना रहे हैं । यह प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ धन लाभ भी देने वाली है। अब वापस बात कम्पनियों के कार्बन क्रेडिट के प्रयोग की करें तो आपका बताते चलें कि स्वेच्छा से खरीदे गए कार्बन क्रेडिट कम्पनियों को उन उत्सर्जन की भरपाई करने में सक्षम बनाते हैं जिन्हें अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। यह उन परियोजनाओं के वित्तपोषण द्वारा किया जाता है जो अन्य स्त्रोतों से उत्सर्जन को कम या उससे बचाते हैं, या जो वायुमंडल से ग्रीनहाउस गैसों को निकालते हैं। एक बड़ा, प्रभावी स्वैच्छिक कार्बन बाजार इन परियोजनाओं के लिए पूंजी के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करेगा, और इस प्रक्रिया में, शुद्ध-शून्य और शुद्ध-नकारात्मक उत्सर्जन लक्ष्यों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस तरह के बाजार की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस (IIF) ने स्वैच्छिक कार्बन बाजारों की स्केलिंग पर एक निजी क्षेत्र की एक टास्क फोर्स की ज़रुरत अनुभव करते हुए 2020 में, मार्क कार्नी ने झ 'टास्क फ़ोर्स ऑन स्केलिंग वोलन्ट्री कार्बन मार्किट' की स्थापना की।

टास्कफोर्स का उद्देश्य एक अभूतपूर्व पैमाने के स्वैच्छिक कार्बन बाजार के निर्माण के लिए एक खाका बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि यह पारदर्शी, सत्यापन योग्य, और मजबूत हो। इस टास्कफोर्स ने 2020 के अंत में एक परामर्श चलाया और अंततः आज, अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की है। जिसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजारों की स्केलिंग या विस्तार बेहद ज़रूरी है। रिपोर्ट में कार्बन क्रेडिट में तीन बातों के विस्तार एवं स्थापना की ज़रुरत पर बल दिया गया है -

- एक सहज, लागत प्रभावी और पारदर्शी में मांग के लिए कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति का मार्ग
- कार्बन क्रेडिट का आदान-प्रदान / लेन-देन में विश्वसनीयता सुनिश्चित करना
- मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए स्केलेबल यानी जो मापा जा सके ऐसा क्योंकि ज्यादातर बड़ी कंपनियां पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 1.5 ° C महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं

इस रिपोर्ट में इस बात पर भी बल दिया गया है कि स्वैच्छिक कार्बन बाजारों में उच्च पर्यावरणीय अखंडता होनी चाहिए और नकारात्मक परिणाम के किसी भी जोखिम को कम करना का रास्ता समहित होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वैच्छिक कार्बन बाजारों को, कंपनियों के स्वयं उत्सर्जन में कमी के प्रयास को विनिवेश या डिस इनसेनटीवाइज़ नहीं करना चाहिए। *द्वारा : निशांत सक्सेना*

अकुशल लोग बेरोजगार होते जायेंगे

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, अप्रैल में रोजगार गंवाने वाले 12.2 करोड़ भारतीयों में से 75 प्रतिशत छोटे कारोबारी और दिहाड़ी मजदूर थे। कारोबार के सामान्य स्तर पर आने के साथ, विश्व ने अपने कामकाज का तरीका बदल लिया है।

नए विश्व में ज्यादा अकुशल असंगठित कामगारों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मशीनों और स्वचालित प्रणालियों ने ज्यादा दक्षता के साथ उनकी जगह ले ली है। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पेश फ्यूचर ऑफ जॉब्स, 2020 रिपोर्ट में कहा गया : ''43 प्रतिशत व्यवसायों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि वे तकनीक एकीकरण के चलते अपने कार्यबल में कमी करने की तैयारी में हैं, 41 प्रतिशत की विशिष्ट कार्यों के लिए अपने यहां ठेकेदारों का उपयोग बढ़ाने की योजना है और सिर्फ 34 प्रतिशत की तकनीक एकीकरण के चलते अपने कार्यबलों की संख्या में विस्तार की योजना है।

मानव और मशीनों द्वारा किए गए वर्तमान कार्यों पर लगने वाला समय समान होगा।'' इस क्रांति की ''तेज गति'' कुछ ऐसी है, जिससे स्पष्ट रूप से भविष्य में अकुशल और कम कौशल वाले लोगों के लिए नौकरियां पैदा होना बंद हो जाएंगी। अनुमान है, कार्यों के इंसान से मशीनों की ओर हस्तांतरित होने के परिणाम स्वरूप 2025 तक 8.5 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गंवा देंगे। दूसरी तरफ, 9.7 करोड़ नई नौकरियां सिर्फ सही कौशल वाले लोगों और मशीनों के लिए ही उपयुक्त होंगी। नई व्यवस्था में आर्थिक संकट की तुलना में नौकरियों से ज्यादा लोगों का विस्थापन देखने को मिलेगा,

शुरुआती जीवन के जीवाश्म दे रहे थे गलत संकेत, प्रयोगों से मिला जवाब

एजेंसियां

शुरुआती जीवन की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिक सूक्ष्मजीवाश्मों पर निर्भर थे, लेकिन ताजा शोध बता रहा है कि इनसे मिली जानकारी भ्रामक कैसे हो सकती है. पृथ्वी पर शुरुआती जीवन बहुत लंबे समय तक सूक्ष्म जीवन था. इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति सर्वव्यापी थी. अभी तक हम जो भी जीवन के विकास के बारे में जानते हैं उसके प्रमाण हमें चट्टनों में मिले हैं जहां अरबों साल पुराने जीवाश्म दबे पड़े थे. इन रिकॉर्ड की हर कोण से आलोचनात्मक रूप से जांच की गई थी फिर भी इन पर सवालिया निशान लग रहे हैं. अध्ययन से पता चला है कि शुरुआती जीवन के ये जीवाश्मों को लेकर सही नतीजे नहीं निकाले गए थे. भूजीवविज्ञानी जूली कोसमिडिस, क्रिस्टीन निम्स और उनके साथियों के नए प्रयोग यह विवाद सुलझाने में मदद कर सकते है कि कौन से सूक्ष्मजीवाश्म शुरुआती जीवन के संकेत हैं और कौन से नहीं . यह अध्ययन जियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है. शोधकर्ताओं ने दर्शाया है कि जीवन संबंधी बैक्टीरिया के दो सबसे आम आकार गोले और फिलामेंट के जीवाश्म जो जैविक कार्बन से बने हैं, जीवों के अनुपस्थिति में भी बन सकते हैं और वे बैक्टीरिया से भी ज्यादा आसानी से संरक्षित हो सकते हैं। कोसमिडिस का कहना है कि जीवाश्म के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि उनकी आकृति विज्ञान बहुत ही सरल होती है और ऐसी बहुत सी अजैविक प्रक्रियाएं हैं जिनसे ये दोबारा बन सकते हैं. यदि आप एक डायनासोर का पूरा कंकाल हासिल करते हैं तो यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया से बनते हैं और उनका रासायनिक क्रियाओं के द्वारा दोबारा बन पाना असंभव है. यह निश्चितता सूक्ष्मजीवों के जीवाश्मों के साथ बहुत ही मुश्किल है

शोधकर्ताओं को उनके कार्य की प्रेरणा कुछ साल पहले दुर्घटनावश हुई एक खोज से मिली थी. इस शोध में कोसमिडिस और निम्स दोनों ही एलेक्सिस टेम्पलटोन की लैब में काम कर रहीं थीं. जब वे कार्बन और सल्फाइड को मिला रही थीं, तब उन्होंने पाया कि गोले और फिलामेंट बनने लगे हैं. उन्हें लगा कि यह बैक्टीरिया गतिविधियों के कारण हो रहा है. ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि वे अजैविक क्रियाओं का नतीजा हैं. कोसमिडिस ने बताया कि बहुत शुरू में उन्हें ये चीजें रासायनिक और आकृति के

तौर पर बैक्टीरिया के जैसी ही लग रही हैं. क्रिस्टीन निम्स ने बताया, ''वे प्रयोग में उपयोग किए बर्तन के तले के बचे हुई पदार्थ की तरह लग रहे थे, लेकिन माइक्रोस्कोप में ये संरचनाएं सूक्ष्मजीवों की तरह लग रहे थे. और वे बहुत ही बेजान हालातों में बने थे इस लिए ये हैरान करने वाले चीजें एक तरह से कहीं से भी निकल कर नहीं आ रही थी. यह काफी रोमांकारी कार्य था। कोसमिडिस ने बताया, ''हमने सोचा कि क्या होता अगर ये प्राकृतिक वातावरण में बनते, क्या होता कि ये चट्टानों पर होता. हमें यह देखने की कोशिश करनी थी कि क्या इनका जीवाश्म बन सकता है या नहीं।

यह देखने की कोशिश में कि क्या ये अजैविक संरचनाएं जिन्हें बायोमॉर्फ कहा जाता है, का बैक्टीरिया की तरह जीवाश्म बन सकता है, निम्स ने नए प्रयोगों के लिए व्यवस्था की. बायोमॉर्फ को सिलिका सॉल्यूशन में मिलाने के बाद शोधकर्ताओं ने शेर्ट नाम के एक सिलिका समृद्ध पत्थर बनाने की कोशिश की. शेर्ट सूक्ष्म जीवाश्म संरक्षित करने में सहसे अग्रणी चट्टानों में से है. उन्होंने कई हफ्तों तक सावधानी से सूक्ष्म स्तर पर जीवाश्म बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्कोप से निगरानी की. उन्होंने पाया कि न केवल उनका जीवाश्म बन सकते है बल्कि उनका अजैविक आकर बैक्टीरिया से भी आसानी से संरक्षित रह सकता है. सूक्ष्मजीवों की हड्डियां और त्वचा नहीं होती है बल्कि ये केवल कीचड़ जैसे जैविक पदार्थ थे. इन्हें सुरक्षित रखने के लिए धीमी गति के प्रकाश संश्लेषण और तेजी से अवसाद जमाव जैसे बहुत खास तरह के हालात होते हैं. ऐसा बहुत ही कम होता है. इनके खोज ने एक स्तर पर जटिलता पैदा करदी . यह जानकर कि ये बिना जीवन के बन सकते हैं और बैक्टिरिया के मुकाबले आसान से संरक्षित हो सकते हैं, इससे शुरुआती जीवन के रिकॉर्ड पर संदेह पैदा होता है. भूजीवविज्ञानी आकृति विज्ञान के भरोसे नहीं चलते इसलिए उन्होंने यहां रसायनविज्ञान का भी सहारा लिया. 8/ 8 जो ऑर्गेनिक एनवोलोप निम्स ने लैब में बनाए थे, वे पृथ्वी की शुरुआती हालात को बनाते हुए बहुत ही उच्च सल्फर वातावरण में बने थे. ऐसे हालातों में पाइराइट बनता है जो आयरन सल्फाइड खनिज है. शोधकर्ताओं के मुताबिक पुरातन चट्टानों में जो सूक्ष्मजीवाश्म दिखते हैं, उनमें प्रायः पाइराइट भी होता है. कॉस्मिडिस का कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम असल सूक्ष्मजीवाश्म की पहचान नहीं कर सकते हैं. बस हमें ज्यादा बेहतर होना होगा.

कोरोना की वजह से पिछले बजट की दो योजनाएं नहीं हो पाई शुरू

पिछले साल बजट में धान्य लक्ष्मी योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन यह योजना शुरू नहीं हो पाई। साल 2020-21 का बजट 1 फरवरी 2020 को पेश किया गया था। इस बजट में कई बड़ी योजनाओं की घोषणाएं की गई थी, लेकिन इनमें से दो योजनाएं कोरोना की वजह से शुरू नहीं हो पाई और उन्हें स्थगित कर दी गई। यह जानकारी 1 फरवरी 2021 में पेश किए गए बजट के बाद सामने आई है।

दरअसल, जब सरकार हर साल अपना बजट पेश करती है तो उसके साथ ही पिछले बजट घोषणाओं की स्थिति की भी जानकारी देती है। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने पर पता चलता है कि सरकार ने पिछले बजट की दो योजनाओं को स्थगित कर दिया। जो दो योजनाएं स्थगित कर दी गई, उनमें से एक कृषि मंत्रालय से जुड़ी है, जबकि दूसरी जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है।

पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि पूरे देश भर में जल संकट एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सरकार ने 100 ऐसे जिले, जहां सबसे अधिक जल संकट है, उसके लिए एक समेकित योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना आदि शामिल था, लेकिन आज सरकार ने बताया कि कोविड-19 की वजह से पिछले साल इस योजना को स्थगित कर दिया गया।

इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि किसान अपनी उपज को स्टोर नहीं कर पाता है, इसलिए उपज खराब हो जाती है या उसे औने पौने दामों में बेचनी पड़ती हे। ऐसे में सरकार ने गांवों में ही फसल के संग्रहण की व्यवस्था करने के लिए धान्य लक्ष्मी नाम की योजना शुरू करने का ऐलान किया था। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा गांवों में स्टोरेज स्कीम शुरू करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन कोरोना की वजह से यह स्कीम भी शुरू नहीं हो पाई।

देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में दो प्रतिशत की वृद्धि

एजेंसियां

देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि केवल कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 7.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी में 11 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) के दौरान वी शेप रिकवरी के संकेत हैं। यानी कि पहली छमाही में जो गिरावट दर्ज की गई थी, दूसरी छमाही में उसमें सुधार होने लगा है। कोविड-19 महामारी के दौरान कृषि की विकास दर में 3.4 फीसदी की वृद्धि होने से जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 17.8 फीसदी से बढ़ कर 19.9 प्रतिशत हो गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 17.8 प्रतिशत थी, जो 2020-21 में 19.9 प्रतिशत हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इससे

पहले 2003-04 में कुल जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 20.77 प्रतिशत थी। इसके बाद लगातार कृषि की हिस्सेदारी कम हो रही है। यहां यह भी खास बात है कि 2000-01 से अगले दो साल तक जबरदस्त सूखा पड़ने के कारण कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। इसके बाद 2003-04 में 9.05 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई थी। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन का रबी की कटाई और खरीफ की बुवाई पर कोई असर नहीं पड़ा।

वी शेप रिकवरी शुरू

रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में जीडीपी में 14.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जबकि दूसरी छमाही में 0.3 फीसदी की मामूली वृद्धि का अनुमान है। लेकिन इन दोनों ही छमाही में कृषि की विकास दर 3.4 प्रतिशत रही। पहली छमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 20.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। जबकि पहली छमाही में सेवा क्षेत्र में दो तिहाई हिस्से वाले होटल, व्यापार, परिवहन एवं सूचना क्षेत्र में 31.5 प्रतिशत की कमी रही, हालांकि अगली छमाही में गिरावट में कमी आई और इन क्षेत्रों में कुल 12 फीसदी की कमी दर्ज की गई।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वैश्विक महामारी की वजह से दूसरे देशों की तरह भारत को संकट का सामना करना पड़ा। 2020-21 से पांच साल पहले तक भारत की औसत वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत थी। 2021-22 में वास्तविक जीडीपी में तेज रिकवरी होने की संभावना है। जो 10 से 12 फीसदी तक रह सकती है, इसके बाद 2022-23 में 6.5 प्रतिशत, 2023-24 में 7 फीसदी वृद्धि का अनुमान है।आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जीडीपी में नॉमिनल ग्रोथ 15.4 फीसदी होगी, जो आजादी के बाद से लेकर अब तक सबसे अधिक रिकॉर्ड होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, अगले वित्त वर्ष के दौरान 1991 के बाद अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सबसे ज्यादा रह सकती है, जबकि नॉमिनल ग्रोथ 1947 के बाद सबसे ज्यादा होगी।

बीएयू के छात्र नितिश का एग्री इंडिया हेकाथोन प्रतियोगिता में चयन हुआ

संवाददाता

रांची : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आ-ईएआरआई) एवं कृषि व किसान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एग्री इंडिया हेकाथोन प्रतियोगिता - 2020 में बीएयू में अध्ययनरत छात्र को सफलता मिली है. इस प्रतियोगिता में देशभर के कृषि विश्वविद्यालयों के कुल 6 हजार कृषि स्नातक छात्रों ने भाग लिया. पहले चरण में आयोजक द्वारा पांच प्रतिशत यानि 3 सौ छात्रों का चयन किया गया है. विवि के कृषि संकाय के सातवें सेमेस्टर

नितिश द्वारा प्रस्तुत छत विस्थापित ग्रीन हाउस तकनीकी

में अध्ययनरत कृषि स्नातक छात्र नितीश कुमार भी चयनित छात्रों में शामिल है.

प्रतिभागियों का चुनाव अभिनव तकनीकी की बाजार में मांग, विचार / नवीनता, मापनीयता, संभावित प्रभाव, तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता, व्यावसायीकरण क्षमता, टीम और समग्र व्यवसाय योजना की नवीनता के आधार पर किया गया है. इस प्रतियोगिता में नितीश कुमार ने कृषि अभियंत्रण विभाग के वैज्ञानिक डॉ प्रमोद राय के मार्गदर्शन में कम लागत के छत विस्थापित ग्रीन हाउस तकनीकी को प्रस्तुत किया। यह तकनीक बीएयू के कृषि अभियंत्रण विभाग में संचालित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना - कृषि संरचना एवं पर्यावरण प्रबंधन में प्लास्टिक अभियांत्रिकी विकसित की गयी है. परियोजना अन्वेंशक डॉ प्रमोद राय ने बताया कि ग्रीन हाउस में सामान्यतः गर्मी के दिनों में अधिक हवा, मिट्टी का तापमान, तथा प्रकाश की तीव्रता इसके उपयोगिता में बाधा उत्पन्न करती है. कम लागत के छत विस्थापित ग्रीन हाउस तकनीक में ग्रीन हाउस (छत को छोड़कर) को युभी स्टैबलाईज कीड़ा रहित जाली (40 मेस) तथा छत को युभी स्टैबलाईज आवरण (200 माइक्रोन) से बरसात एवं जाडे के दिनों में तथा शेडनेट आवरण से गर्मी के दिनों में ढकते है. इस ग्रीन हाउस का उपयोग करके सालों भर सब्जियों की खेती या प्लास्टिक ट्रे में विषाणुरहित स्वास्थ्य सब्जियों के पौधे उगाये जा सकते है. इस तकनीक के बारे में युटूइब लिंक https://youtu.be/fy1U3Y75918 पर विडियो पर देखा जा सकता है.। डॉ राय ने जानकारी दी कि दुसरे चरण में 3 सौ छात्रों में से 24 छात्रों का चयन किया जायेगा. सभी 24 सफल छात्रों को एक लाख की राशि तथा कृषि आधारित कंपनी स्थापित करने में कृषि व किसान मंत्रालय, भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पहले चरण की सफलता तथा दुसरे चरण में प्रवेश के लिए कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह, डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव, विभागाध्यक्ष प्रो डीके रूसिया ने नितीश को बधाई दी है।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में सीमित आपूर्तिकर्ता वाले मदों की प्रदर्शनी हॉल का उद्घाटन

रांची: 28जनवरी क्को मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में सीमित आपूर्तिकर्ता वाले मदों की प्रदर्शनी कक्ष (हॉल) का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी कक्ष मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रथम तल पर भंडार कार्यालय के पास स्थित है।रेलवे के दैनिक परिचालन में अनुरक्षण के कार्य के लिए कई प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है । इनमें से कई सामग्री ऐसी होती है, जिन्हें केवल अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदा जाता है । । इस प्रकार की सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, हटिया में एक प्रदर्शनी कक्ष स्थापित किया गया है, जहाँ इस प्रकार के मदों को रखा गया है तथा मदों के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी गई है। स्थानीय निर्माता इस प्रदर्शनी को देख कर सामग्री की जानकारी एवं पंजीकरण कराने संबंधी प्रक्रिया जान सकते हैं ।

सीएमपीडीआई परिवार के 6 सदस्यों को सम्मानित किया गया

रांची संवाददाता :सीएमपीडीआई परिवार के 6 सदस्यों को आज संस्थान के ''कांफ्रेंस हॉल'' में आयोजित एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। इनमें श्री अरूण मजुमदार- मुख्य प्रबंधक (खनन),सर्वेश प्रसाद-मुख्य प्रारूपक, नित्यानंद घोष-मुख्य प्रारूपक, मो0 अख्तर-सहायक पर्यवेक्षक, श्री छोटु सिंह-कनीय बेयरर एवं दिनेश्वर महतो-वरीय एसी ऑपरेटर शामिल हैं।

इस मौके पर सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन ने सेवानिवृत्त कर्मियों को पुष्पगुच्छ, मान-पत्र, प्रतीक चिह्न व शॉल देकर कम्पनी की ओर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन एव ंनिदेशक (तकनीकी/सीआरडी) एस0 के0 गोमास्ता ने सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, सुखी एवं दीघार्यु जीवन की कामना की। श्रमिक प्रतिनिधि के0बी0 शिरोमणि एवं प्रलय एवं सीएमओएआई के प्रतिनिधि अभिषेक कुमार ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए। मंच का संचालन तथा धन्यवाद ज्ञापन वरीय प्रबंधक (कार्मिक) नवीन कुमार सिन्हा ने किया।

आम बजट देशहित में नहीं: डॉ.सहदेव राम

रांची : आम बजट से सरकारी कर्मचारियों, शिक्षित बेरोजगारों, मजदूरों में घोर निराशा हुयी है। इस बजट में सरकार ने बंद पड़े प्रतिष्ठानों को खोलने, सरकारी संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के लिये कोई योजना नहीं बनायी है। रोजगार को बढावा देने के लिये कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है। सरकारी संस्थाओं का निजिकरण हो चुका है उसके बाद भी बीमा, सरकारी बैंको एवं सरकारी संस्थाओं के निजिकरण से देश में अलग तरह की बेरोजगारी उत्पन्न होगी और इससे देश में भ्रष्टाचार, असंतोष, पदलिप्सा एवं महंगाई जैसी बुराइयों से देश त्रस्त होगा। उक्त बातें केंद्रीय कर्मवारी एवं अधिकारी परिसंघ के अध्यक्ष डॉ. सहदेव्प राम ने कही।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारियों के लिये आयकर में छूट की सीमा नहीं बढाने के कारण लोगों में उदासीनता व्याप्त है। वहीं पेंशनधारियों को आयकर में रिटर्न छूट नहीं देने से सरकार के प्रति निराशा बढी है। हम सभी केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगी इस बजट के प्रति अपनी उदासीनता प्रकट करते हैं।

.....पेज एक का शेष

6.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है समुद्र का तापमान

यह अध्ययन बुलिटन ऑफ़ द अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

हीटवेव की घटनाएं पहले से ही हो रही है, जिसमें पूर्वोत्तर प्रशांत के 2019 के हीटवेव को ही ले लो। कमजोर हवाओं और हवा के अधिक तापमान ने प्रशांत महासागर के पानी को लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। शोधकर्ताओं ने बताया कि एक पतली मिश्रित परत ने पानी के गर्म होने में अहम योगदान दिया है और यह बदतर होता जाएगा।

अमाया ने बताया कि यदि आप 2019 जैसी हवा और समुद्र की स्थिति लेते हैं और यदि उन्हें 2100 में अनुमानित मिश्रित परत पर लागू करते हैं, तो इससे एक समुद्री हीटवेव उत्पन्न होगी। इसका तापमान 2019 की तुलना में 6.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। इस तरह की घटना अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को पूरी तरह से तबाह कर देगी। अमाया यह भी बताती है कि जैसे-जैसे जलवायु गर्म होती जा रही है और मिश्रित परत पतली होती जा रही है, वैज्ञानिकों को साल-दर-साल समुद्र की सतह के तापमान के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है। समुद्र के तापमान का सटीक अनुमान लगाने की क्षमता के बिना, मत्स्य पालन और अन्य तटीय संचालन खतरे में आ सकते हैं।

फसल सुधार में जीनोम एडिटिंग टूल्स अधिक कारगर : डॉ कुतुबुद्दीन अली मोला

रांची संवाददाताः बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में गुरूवार को इंडियन सोसाइटी ऑफ़ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, रांची चैप्टर ने क्रिस्पर कस - अगली पीढ़ी के सटीक प्रजनन टूल्स विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया. इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता आईसीएआर- नेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट, कटक के बायोटेक्नोलॉजिस्ट डॉ कुतुबुद्दीन अली मोला थे. डॉ मोला ने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी तकनीक से कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव आने जा रहा है. ग्लोबल मांग के अनुरूप फसल सुधार में पौधा प्रजनकों को इन तकनीकों की दिशा में कार्य किये जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि क्रिस्पर कस तकनीक फसल सुधार हेतु अगली पीढ़ी के लिए सटीक प्रजनन टूल्स के रूप में उभर के सामने आया है. इस जीनोम एडिटिंग तकनीक से विभिन्न फसलों में प्रजनन से अधिक जीन विशेषताओं सटीक रूप से सुधार कर सकते हैं. इस सटीक प्रजनक टूल्स से एक वर्ष या कुछ ही वर्षो फसल सुधार संभव है, जबकि पारंपरिक साधनों के माध्यम से इसे लंबे वर्षों में किया जा पाना संभव था.

डॉ. मोला ने कहा कि यह तकनीक प्रतिरोधी फसल किस्म का विकास कर सकता है. इससे उपज बढ़ाया सकता है और विषम जलवायु में स्मार्ट फसलें पैदा की जा सकती है. हमें उम्मीद है कि सरकार ग्रामीण और विकास के क्षेत्र में इस

दिशा पर जोर देगी. मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष एवं कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों को ग्लोबल मांग एवं बदलते नवीनतम तकनीकी पर अद्यतन शोध जारी रखने की जरूरत है. क्रिस्पर कस की बायोटेक्नोलॉजी तकनीक तीव्र फसल प्रजनन और लाभकारी फसल विशेषताओं के विकास में कारगर टूल्स सिद्ध हो सकती है. सोसाइटी के सचिव डॉ जेडए हैदर ने इस व्याख्यान को पीजी एवं पीएचडी छात्रों के शोध में काफी उपयोगी बताया. व्याख्यान में डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर सहित बड़ी संख्या में पीजी एवं पीएचडी छात्र -छात्राओं ने भाग लिया।

सीसीएल में सेवानिवृत कर्मियों को भावभीनी विदाई

रांची संवाददाता : सीसीएल मुख्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों सर्वश्री अनिल कुमार सिंह, महाप्रबंधक (ई. एण्ड एम.),सतर्कता विभाग; मो. जावेद अक्तर, मुख्य प्रबंधक (वित्त), वित्त एफपीसी विभाग; ललन कुमार, वरीय प्रबंधक (कार्मिक),पेंशन विभाग; राजेश कुमार सिंह, वरीय प्रबंधक (माईनिंग) एनआईएमसी विभाग; मो. ऑन खान, वरीय डीईएस 'ए-1, सांख्यिकी विभाग; जयेश रावल, जनसम्पर्क सहायक 'ए-1', जनसम्पर्क विभाग; मो. असमुदिन, वरीय डीईएस 'ए-1', प्रणाली विभाग; अब्दूल बारी, मुख्य डी/मैन 'ए-1', पी एंड पी विभाग; मो. खालिक, वरीय निजी सहायक, वित्त विभाग; श्याम सुन्दर प्रसाद, स्टेनोग्राफर, जेएसएसपीएस; इरसाद अली, सहायक फॉरमैन, ई एंड एम विभाग; सुकरा उरांव, फिटर हेल्पर, नगर-प्रशासन विभाग तथा केन्द्रीय अस्पताल गांधीनगर से डॉ. बंसत नारायण, सीएमओ; डॉ. हरि चरण मुर्मू, उप-सीएमओ; डॉ. अलेक्जेंडर टोप्पो, चिकित्सा अधीक्षक; अश्रिता कुजूर, मैट्रन 'ए-1'; उर्सिला मिंज एवं मैट्रन 'ए-1'; समापिका दास, मैट्रन 'ए-1' को सीसीएल परिवार की ओर से सीसीएल मुख्यालय में ''सम्मान समारोह'' का आयोजन कर भावभीनी विदाई दी गई।

सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने सेवानिवृत कर्मियों को संबोधित करते हुये कहा कि आज आप अपने लंबे अनुभवों के साथ आज सेवानिवृत हो रहे हैं। मैं आप सभी को कंपनी की ओर से दूसरी पाली के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आपके स्वस्थ्य एवं सुखद जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कहा कि आप सभी हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। इस अवसर पर भोला सिंह, एन.के. अग्रवाल,एस.के. सिन्हा ने सभी सेवानिवृत हो रहे कर्मियों को शुभकामनाएं दीं। महाप्रबंधक (कल्याण) डॉ. ए.के. सिंह ने सेवानिवृत कर्मियों का कंपनी की ओर से स्वागत

भारत के बाद अब पाकिस्तान ने दिया बासमती को जीआई टैग

पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय फोरम में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए एक लंबे इंतजार के बाद बासमती चावल का जीआई पंजीकरण किया है लेकिन जानकारों का कहना है कि भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

पाकिस्तान ने एक दशक से भी ज्यादा इंतजार के बाद बासमती चावल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग दिया है। पाकिस्तान का यह कदम भारत के उस आवेदन के बाद उठाया गया है, जिसमें भारत ने यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान से अलग अपने बासमती के लिए विशेष जीआई टैग की मांग की गई थी। भारत ने मई, 2010 में अपने यहां सात राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ भागों में बासमती को जीआई टैग दिया था।

किसी उत्पाद को उसके उत्पत्ति की विशेष भौगोलिक पहचान से जोड़ने के लिए जीआई टैग दिया जाता है ताकि वह उत्पाद अलग और खास बन सके। पाकिस्तान के बासमती चावल उत्पादक इसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे। दरअसल पाकिस्तान में जीआई पंजीकरण के लिए कानून की जद्दोजहद करीब दो दशक से चल रही थी, जिसे हाल ही में अमलीजामा पहनाया गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के वाणिज्य एवं निवेश मामलों के सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाउद ने 26 जनवरी, 2021 को अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, 2020 के तहत बासमती चावल को जीआई में पंजीकृत कर लिया है। आधिकारिक ईयू जर्नल में बताया गया है कि 11 सितंबर, 2020 को भारत ने

अपने यहां पैदा होने वाली बासमती के लिए विशेष भौगोलिक पहचान (एक्सकलूसिव ज्योग्राफिकल इंडिकेशन) के लिए आवेदन किया था। भारत ने अपने बासमती की अहमियत बनाए रखने के लिए यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान से अलग होकर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग की मांग की थी।

वहीं, बासमती का जीआई पंजीकरण न होने के कारण भारत के इस आवेदन के बाद पाकिस्तान को यह चिंता सताने लगी थी कि जीआई टैग के बिना उसका बासमती कहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में पूरी तरह से बाहर न हो जाए, क्योंकि 2006 में ईयू की अनुमति के बाद भी पाकिस्तान ने अब तक अपने बासमती को जीआई टैग में पंजीकृत नहीं किया था। उनका जीआई कानून बीते दो दशक से लंबित था। अब पाकिस्तान में जीआई एक्ट, 2020 के तहत जीआई रजिस्ट्री बनाई गई है जो कि जीआई पंजीकरण का काम करती है। रज्जाक दाऊद ने आगे लिखा है कि इस कदम से हमारे उत्पाद का बेजा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके बामसती को संरक्षण भी मिलेगा। उन्होंने अपने लोगों से इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उत्पादों के सुझाव भी मांगे हैं।

भारत-पाकिस्तान दायरे में हिमायल के कुछ खास भौगोलिक निचले क्षेत्रों में ही बासमती पैदा होती है। इस भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु ही इसे एक अनूठा स्वाद -सुगंध और आकार देती है, जिसकी अच्छी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में है। कई ऐसे चावल अब दुनिया भर में पैदा होते हैं जो लंबे दाने वाले होते हैं लेकिन उनमें कोई विशेष सुगंध नहीं होती है। इसलिए बासमती का महत्व अब भी बना हुआ है। बासमती चावल के निर्यातक और चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के चेयरमैन विजय कुमार सेतिया ने कहा कि 2006 में जीई टैग को लेकर भारत-पाकिस्तान का मामला यूरोपियन यूनियन में पहुंचा था। वहां, पर जीआई टैग मान्यता के लिए भारत ने अपने बहुत ही खास और वैज्ञानिक मानकों पर बासमती उत्पादकों में सात राज्यों की सूची दी थी जबकि पाकिस्तान ने अपने बहुत ही छोटे भौगोलिक हिस्से में पैदा होने वाली बासमती के लिए सिर्फ 14 जिलों के नाम ही गिनवाए थे। अब पाकिस्तान ने इन्हीं 14 जिलों में, जहां बासमती पैदा की जाती है उसको अपने देश में जीआई मान्यता दे दी है। सेतिया ने कहा कि यह भारत के लिए काफी अच्छा है क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा परिभाषित कर दी है और भारत का बहुत बड़ा भू-भाग है जो बासमती जीआई के दायरे में है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की बासमती का दबदबा बना रहेगा। अंतरराष्ट्रीय लड़ाई में भी पाकिस्तान शायद भारत से अब कमजोर भी पड़ जाए।

वर्ष 2006 में ईयू के सामने भारत ने बासमती की गुणवत्ता को सर्वोपरि रखते हुए जीआई सूची से उस वक्त राजस्थान को भी बाहर कर दिया था, जबकि मध्य प्रदेश बासमती के जीआई टैग को लेकर कुछ वर्षों से अपना दावा कर रहा है। जानकारों का कहना है कि यदि बासमती का दायरा विशेष और जलवायु मानकों पर सीमित नहीं होगा और एक के बाद एक राज्य दावा करेंगे तो बासमती की गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बड़ा झटका लगेगा। इसी तरह से पाकिस्तान यदि अब अपने जीआई टैग के भौगोलिक दायरे को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसे भी एक बड़ा झटका मिल सकता है। हालांकि, पाकिस्तान के भीतर यदि कोई जिला अब नए सिरे से जीआई क्लेम करेगा तो कलह वहां भी बढ़ सकती है।

फोटो न्यूज

चार पंख और चार आंखें

फोटो : संजय ढलैत

तितलियों के पंखों की खूबसूरती उनकी सुरक्षा भी करती हैं। इनके पंखों पर आंख जैसी बनावट खूबसूरती के साथ ही आंखों के होने और देखने का भ्रम भी पैदा करती है। इससे शत्रुओं से उनका बचाव भी होता है?

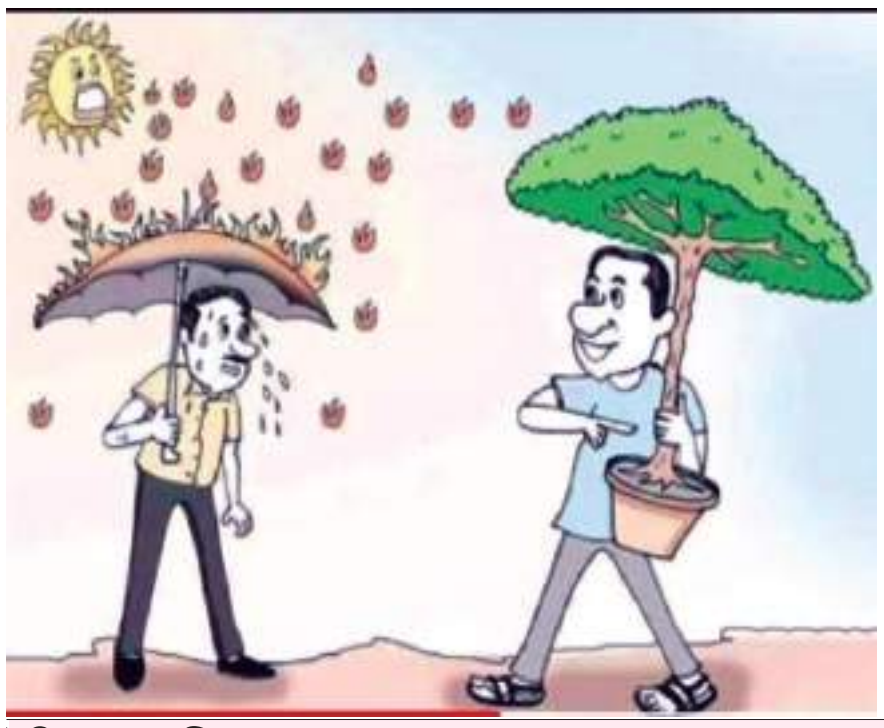

खत्म हुए शिकारी तो तिगुनी हुई बाघों की संख्या

एजेंसियां

पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बहुत कम समय में बाघों की संख्या को दोगुने से अधिक करने के लिए वैश्विक स्तर के पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्ष 2014 में यहां 23 के करीब बाघ थे जिनकी संख्या 2018 में बढ़कर 65 हो गयी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व बाघों के मद्देनज़र एक बेहतरीन वातावरण उपलब्ध कराता है। बावजूद इसके यहां इनकी संख्या नहीं बढ़ रही थी क्योंकि इनका अवैध शिकार निरंतर जारी था।

वैश्विक स्तर पर बाघों को बचाना एक चुनौती है। बीसवीं सदी की शुरुआत में विश्व में करीब 1,00,000 मौजूद थे। लेकिन बेतहाशा शिकार की वजह से बाघों की संख्या 95 फीसदी घट कर वर्ष 2010 में महज 3, 200 रह गयी। माना जाता है कि बाघ की दहाड़ करीब तीन किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। विडंबना यह है कि अपनी बहादुरी के लिए चर्चित यह सुंदर जीव भी खतरे में है। पूरे विश्व में बाघों की संख्या घटकर कुछेक हजार पर सिमट गई है। ऐसी स्थिति कैसे आई और कैसे पुरानी स्थिति बहाल हो– इस वैश्विक समस्या और उसके समाधान का एक छोटा सा नमूना पेश करता है पीलीभीत का टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है।

वर्ष 2014 में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित इस टाइगर रिजर्व में महज 23 बाघ मौजूद थे। टाइगर रिजर्व घोषित होने के महज चार सालों बाद यहां बाघों की संख्या बढ़कर 65 हो गयी। इस उपलब्धि के लिए बीते नवंबर माह के 23 तारीख को पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार टीएक्स2 से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार वैश्विक स्वयंसेवी संस्था वर्ल्ड वाइड फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ), यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी), अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन)

और अन्य संस्थाएं मिलकर देती हैं। टीएक्स2 का तात्पर्य है 'टाइगर्स टाइम टू' जो बाघों की संख्या को दोगुना करने के लक्ष्य को दर्शाता है।

बाघों की संख्या को दोगुना करने के लक्ष्य की भी एक कहानी है। बीसवीं सदी की शुरुआत में विश्व में करीब एक लाख बाघ मौजूद थे। एक समय में बाघ एशिया के लगभग हर हिस्से में पाए जाते थे। पूर्वी तुर्की से लेकर, तिब्बती पठार तक। उत्तरी ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान के सिंधु घाटी का क्षेत्र और अन्य जगहों पर भी बाघ देखे जा सकते थे। लेकिन बेतहाशा शिकार की वजह से बाघों की संख्या में 95 फीसदी से भी अधिक की कमी आई और 2010 में दुनिया में महज 3, 200 बाघ रह गये। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 से 2014 के बीच 380 बाघों के खाल जब्त किए गए। बाजार में इनकी कीमत करीब 29 करोड़ 60 लाख रुपये लगाई गयी थी। वैसे तो यह रकम कुछ खास नहीं है पर अगर बाघों के कुल मौजूदा संख्या के लिहाज से देखा जाए तो इसकी व्यापकता का अंदाजा होता है। जंगली जानवरों के अवैध व्यापार पर आधारित इस रिपोर्ट में यह बात कही गयी है।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के तराई क्षेत्र में हरियाली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे बाघ शान से रहते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व घोषित होने के शुरुआती दो साल के भीतर ही अवैध शिकार के मामले में 71 अभियुक्तों को जेल भेजा गया और बाघों की संख्या बढ़ने लगी। इसी साल यानी 2010 में 13 देशों की सरकारों ने मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग समिट में 2022 तक बाघों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना करने का निर्णय लिया। इन तेरह देशों में ही तब बाघ मौजूद थे। इसी लक्ष्य को हासिल करने पर यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है।

बाघ थे अवैध व्यापार के शिकार

इस मुद्दे के जानकार बताते हैं कि तराई क्षेत्र में हरियाली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसकी वजह से यहां शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, नीलगाय इत्यादि भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। मांसाहारी बाघ को और क्या चाहिए! पीने का पानी और जरूरत भर भोजन। बस बाघों की सुरक्षा होती रहे तो बाघ बचे रहेंगे, कहते हैं कैलाश प्रकाश जो 2018 तक पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वन अधिकारी रहे। इनके अनुसार टाइगर रिजर्व घोषित होने के पहले बाघों का अवैध शिकार यहां की सबसे बड़ी समस्या थी। उसको नियंत्रित किया गया तो बाघों की संख्या बढ़ने लगी। रूहेलखण्ड जोन के अंतर्गत आने वाले पीलीभीत वन प्रभाग को 28 फरवरी 2014 वन्य विहार तथा दिनांक 9 जून 2014 को पीलीभीत टाईगर रिजर्व घोषित किया गया।

भ्रष्टाचार में भारत 86 वें नंबर पर

एजेंसियां

करप्शन पर्सेप्शन्स इंडेक्स 2020 में भारत को 180 देशों की सूची में 86वें पायदान पर रखा गया है। गौरतलब है कि हर साल दुनिया भर में भ्रष्टाचार की स्थिति को बताने वाला यह इंडेक्स ट्रांस्पेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में भारत को कुल 40 अंक दिए गए हैं। वहीं 2019 के लिए जारी इंडेक्स को देखें तो उसमें भारत को 41 अंकों के साथ 80वें पायदान पर रखा था। जो दिखाता है कि देश में भ्रष्टाचार की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

यदि अन्य दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो भूटान की स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर है, वो 68 अंकों के साथ 24वें स्थान पर है। इसके बाद मालदीव का नंबर है जो 43 अंकों के साथ 75वें स्थान पर है। इसके बाद भारत (86), श्रीलंका (94), नेपाल (117), पाकिस्तान (124) और फिर बांग्लादेश (146) का नंबर आता है जोकि दक्षिण एशिया का सबसे भ्रष्ट देश है।

यदि इंडेक्स की मानें तो पिछले करीब एक दशक में अधिकांश देशों ने भ्रष्टाचार से निपटने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं की है। दुनिया के करीब दो तिहाई देशों के अंक 50 से कम हैं। इस इंडेक्स को 1 से 100 अंकों के बीच में बांटा गया है, जिसमें 100 का मतलब सबसे कम भ्रष्ट जबकि 1 का मतलब सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। हालांकि किसी भी देशो को 100 में से 100 अंक नहीं मिले हैं। डेनमार्क और न्यूज़ीलैंड हैं सबसे साफ सुथरी छवि वाले देश इस इंडेक्स में कुल 88 अंकों के साथ न्यूज़ीलैंड और डेनमार्क को पहले स्थान पर रखा गया है।

साग सिर्फ भोजन ही नहीं औषधी भी

मनोरंजन सिंह

झारखंड में साग का एक विशेष महत्व है। यहां के कई इलाकों में तो भोज के अवसर पर साग परोसे बगैर उसे पूर्ण माना ही नही जाता। यह हम झारखंडियों का सौभाग्य भी है कि यहां सैकड़ो किस्म के साग उपलब्ध हैं। जिनका औषधीय महत्व भी है।

बचपन से ही हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए हमेशा प्रेरित किया जाता रहा है। इसका मुख्य कारण इन शाक-सब्जियों में निहित पोषक तत्व हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद आवश्यक हैं। चौदह शाक में उपयोग किए जाने वाले शाकों के औषधीय गुणों की पुष्टि वैज्ञानिक शोधों से भी होती है। इंटरनेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल जर्नल में वर्ष 2017 में प्रकाशित एक अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि इन शाकों के सेवन से श्वसन संबंधी मौसमी बीमारियों से तो बचाव होता ही है, साथ ही यह दमा, बुखार, गैस्ट्रिक इत्यादि रोगों से बचाता है। वर्ष 2007 में जर्नल ऑफ मेडिसिनल एरोमैटिक प्लांट साइंस बायोटेक में प्रकाशित एक शोध के अनुसार घेटू साग का सेवन बुखार, दमा एवं ब्रोंकाइटिस के उपचार में कारगर है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लाइफ साइंस एंड फार्माकॉलॉजी रिसर्च में वर्ष 2012 में प्रकाशित एक शोध बताता है कि सुशनी साग हमारी तंत्रिका तंत्र के लिए एक टॉनिक का काम करता है और अनिद्रा भी दूर करता है।

वर्ष 2011 में फार्माकॉलॉजी ऑनलाइन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बथुआ साग न सिर्फ लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, बल्कि पैरासिटामोल के अत्यधिक सेवन की वजह से विकृत लीवर को ठीक भी कर सकता है। इसी प्रकार चौदह शाक में उपयोग होने वाले आंय शाकोन का भी अपना-अपना औषधीय महत्व है।

पीएम किसान सम्मान : 20 लाख से अधिक नकली किसानों ने उठाया लाभ

1,364 करोड़ रुपए की धनराशि

सूचना के अधिकार के पता चला है कि 31 जुलाई 2020 तक 20.48 लाख से अधिक ऐसे लोगों को योजना का फायदा पहुंचाया गया जो इसके हकदार नहीं थे

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले घोषित की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जमकर बंटरबाट हुई है। सूचना के अधिकार के पता चला है कि 31 जुलाई 2020 तक 20.48 लाख से अधिक ऐसे लोगों को योजना का फायदा पहुंचाया गया जो इसके हकदार नहीं थे। इन लोगों के बैंक खातों में कुल 1,364.13 करोड़ रुपए भेजे गए।

गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना उन लघु और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास दो एकड़ से कम जमीन है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारियां बताती हैं कि योजना का लाभ लेने वाले आधे से अधिक (55.58 प्रतिशत) ऐसे अपात्र लोग हैं जो आयकर देने वालों की श्रेणी में शामिल हैं और शेष 44.41 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो योजना के हकदार नहीं हैं।

पंजाब में सबसे अधिक नकली किसान

सबसे अधिक अपात्र लोगों को पीएम किसान निधि का फायदा पंजाब में मिला है। यहां 4.74 लाख (23.16) अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिला। दूसरे पर नंबर पर असम है जहां 3.45 (16.87 प्रतिशत) लाख गलत लोगों ने इस निधि का पैसा भेजा गया। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य है जहां 2.86 लाख अपात्र लोगों के खाते में पैसे भेजे गए। इन तीन राज्यों में कुल 54.03 प्रतिशत अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिला।

अगर खत्म हो गई तितलियां ?तो चॉकलेट, सेव कॉफी भी नसीब नहीं होंगे

एजेंसियां

रंग-बिरंगी सुंदर तितलियां के बारे में कभी आपने सोचा है कि अगर ये पृथ्वी से खत्म हो गईं तो क्या होगा? तितलियां न रहे तो इंसानों को चॉकलेट नसीब न हो. लोग सेब का स्वाद भी नहीं ले पाएंगे, यहां तक की कॉफी भी नसीब नहीं होगी। ऐसे कई फल हैं जिनके फूलों का रस पीकर तितलियां परागण की क्रिया करती हैं जिससे फूल, फल में बदलता है।

अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे का यह मानना है कि अगर तितलियां और मधुमक्खियां खत्म हो गईं तो इसका असर 75 प्रतिशत अमेरिकी फलों पर होगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी अनुमान है कि दुनियाभर की 75 फीसदी खेती परागण पर निर्भर करती है। परागण में मधुमक्खी, तितली, छोटे पक्षी और कई तरह के कीट मदद करते हैं। पौधों में पराग कण का नर-भाग से मादा-भाग पर स्थानातरण परागण कहलाता है। इसे अंग्रेजी में पॉलिनेशन कहते हैं।

देहरादून के तितली ट्रस्ट से जुड़े विशेषज्ञ संजय सोंधी ने तितलियों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि तितलियों का स्थान परागण में मधुमक्खियों के बाद आता है। ''मधुमक्खियों के अलावा कई कीट-पतंगे और तितलियां भी परागण करती

हैं। इसके अलावा भी इको सिस्टम और फूड चेन में तितलियों का योगदान है,'' सोंधी कहते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र यानी इको सिस्टम में एक महत्वपूर्ण अंग है फूड चेन। फूड चेन का मतलब पृथ्वी का हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है और एक के खत्म हो जाने से इसका प्रभाव दूसरे जीवों पर पड़ता है। इसे समझाते हुए सोंधी कहते हैं, ''तितलियां न सिर्फ परागण करती हैं बल्कि उनके अंडे से बने लार्वा (कैटरपिलर) और प्यूपा कई दूसरे जीवों का भोजन होते हैं। कई चिड़िया अपने बच्चों को कैटरपिलर खिलाकर ही पालती है। सांप और दूसरे कई और कीट तितलियों को खाते हैं। कहते हैं कि तितली के 100 अंडो में से तीन ही वयस्क बन पाते हैं, बाकी किसी न किसी जीव का भोजन बन जाते हैं,'' सोंधी कहते हैं। ऐसे में अगर तितलियां खत्म हुईं तो दूसरे जीवों के संरक्षण पर भी असर होगा।

सरकारों के बीच विज्ञान, जैवविविधता और अर्थव्यवस्थाओं पर बन रही नीतियों पर काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था आईपीबीईएस ने वर्ष 2017 की रिपोर्ट में खेती में परागण के महत्व का आंकलन किया। इस रिपोर्ट में भारत से वर्ष 2007 का आंकड़ा शामिल किया गया है जिसके मुताबिक भारत में एक हेक्टेयर खेती पर 804 डॉलर (करीब 60 हजार रुपए) का लाभ परागण की वजह से होता है।

खूबसूरती ही बन गई तितलियों की सबसे बड़ी दुश्मन

तितली की खूबसूरती इनके जान की दुश्मन बन गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः सजावट के लिए इनका शिकार कर इन्हें बेचा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 1998 से 2007 के बीच दक्षिण-पूर्व एशिया से तीन लाख तितलियों को दूसरे देशों में भेजा गया।

जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ष 2005 में तितलियों को लेकर एक किताब 'बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया' प्रकाशित की थी। इस किताब के लेखक आईजे गुप्ता और डीके मंडल लिखते हैं कि विश्व में तितलियों का कारोबार 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। भारत की मुद्रा में अभी यह 7.3 खरब रुपया होता है।''भारत से हर महीने 50 हजार से अधिक तितलियों की तस्करी होती है। इनका शिकार पश्चिमी हिमालय (हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग) पूर्वी हिमालय (सिक्कम और पूर्वी बंगाल का इलाका) में सर्वाधिक होता है,'' किताब ने तितली के व्यापार को समझाते हुए लिखा है। तितलियों का इस्तेमाल दीवार पर शो पीस की तरह टांगने, ऐश ट्रे बनाने और दूसरी सजावट के सामानों में होता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक तितलियों का कारोबार 1990 के दौरान बढ़ा।

शहरों में तापमान से प्रभावित हो रहा स्वास्थ्य

अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन से कारण हैं जिनसे शहरी गर्मी बढ़ रही है जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा हैं।

पिछली आधी सदी में दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में गर्मी की चरम घटनाओं ने अपना स्वरुप बदला है, ऐसी घटनाएं जो अब एक सदी पहले की तुलना में सौ गुना अधिक हो रही हैं। सभी प्राकृतिक आपदाओं में से, अत्यधिक तापमान की घटनाएं मौसम से संबंधित मृत्यु दर का मुख्य कारण हैं। बढ़ती तापमान की घटनाएं आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अतिरिक्त मौतों के लिए मुख्य कारण माने जा सकते हैं।

शहरों में गर्मी का प्रभाव वनस्पति वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों के भीतर स्थितियां सभी हिस्सों में समान नहीं हैं। उनके या तो प्राकृतिक रूप के कारण या निवासियों की विशिष्ट आवश्यकताओं या कमजोरियों के कारण, इसलिए शहर के सभी जिलों में हीटवेव का प्रभाव समान नहीं होता हैं। इस प्रकार उन क्षेत्रों की पहचान करना जो विशेष रूप से गर्मी के तनाव की चपेट में हैं, वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर हीटवेव के प्रभावों को दूर करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप करना महत्वपूर्ण है।

अध्ययन जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन से कारण हैं जिनसे शहरी गर्मी बढ़ रही है जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा हैं। विश्लेषण ने इस विषय पर बड़े-बड़े चालीस अध्ययन का चयन किया है, 'स्कोपस और पबमेड' के दो प्रसिद्ध डेटाबेस से निकाले गए हैं। अध्ययन यह पता लगाने के लिए है कि वे कौन से लक्षण है जो लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और तनाव को कम करने में आड़े आ सकते हैं। इस विश्लेषण में अध्ययनकर्ताओं ने उन कारणों को भी जोड़ा है जो इस तरह के वातावरण का निर्माण करते हैं। क्योंकि तापमान से संबंधित मृत्यु दर का संबंध एक क्षेत्रीय आधार पर नहीं होता है। बल्कि, यह शहरी बनावट से जुड़ा है, जहां प्राकृतिक, शारीरिक और सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं का परस्पर प्रभाव पड़ता है। बढ़ती घटनाएं (एन्हांस्ड एक्सपोजर) की अवधारणा के माध्यम से, अध्ययन में पता चला है कि शहरों के विभिन्न स्थानों के अंदर प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न पहलुओं को कैसे बढ़ाया या कम किया जा सका है। शहर की जनसंख्या के गर्मी के सम्पर्क में आना शारीरिक जोखिम से जुड़ा हुआ है। शहरों के भीतर निर्मित क्षेत्र दिन के दौरान सौर ऊर्जा एकत्र करते हैं और रात के दौरान इसे छोड़ देते हैं। इसलिए शहरी क्षेत्र में रात के दौरान भी आसपास के पेड़ों वाले क्षेत्रों की तुलना में जहां पेड़ नहीं हैं ऐसे क्षेत्र अधिक गर्म रहते हैं।

सीएमसीसी में शहरी योजनाकार और शोधकर्ता मारग्रेट ब्रील कहते हैं यह शहरों के उनके आकार और डिजाइन के आधार पर अधिक या कम गर्म होता है। लेकिन हम इस घटना के साथ केवल प्राकृतिक जोखिम पर विचार नहीं कर सकते हैं, जिसे "हीट आइलैंड" के रूप में जाना जाता है। अन्य स्थितियां जो जीना मुश्किल बना सकती हैं, और इससे भी घातक हो सकती हैं।

जैसा कि अध्ययन से पता चलता है, सामाजिक नुकसान गर्मी के खतरे को और अधिक बढ़ा सकते हैं। वहां लू (हीटवेव) से जुड़ी मृत्यु दर अधिक है जहां अपराध अधिक है और सामाजिक सामंजस्य कम है। दूसरी ओर यह विस्तृत पारिवारिक संबंधों की विशेषता वाले समुदायों में कम पाया गया जो अलग रहने के बजाय पारस्परिक देखभाल में विश्वास करते हैं। यह अध्ययन अर्बन क्लाइमेट नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ हैं।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in

Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511

Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm

SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।